



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रधारा १

EXTRAORDINARY

भाग II—लेख ३—उपलब्ध (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई विल्सी, शनिवार, नवंबर 7, 1970/कार्तिक 16, 1892

No. 192] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1970/KARTIKA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह ग्रन्ति संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1970

G.S.R. 1876.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service in the Food Corporation of India, established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), would prejudicially affect the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community and would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares service in the Food Corporation of India to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. F. 10-3/70-FCC.]

K. P. MATHRANI, Secy.

(८३)

आश्र. नुवि. सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(खात्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1970

सां. का० नि० 1876.—प्रावश्यक सेवाएँ प्रतुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 597 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करते हुए कन्द्रीय सरकार यह राय होने के कारण कि खात्र निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) के अधीन स्थापित भारतीय खात्र निगम को किसी भी सेवा में हड्डियाल होने से सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएँ बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे समृद्धि के लिए भारी कठिनाई पैदा होगी, एतद्वारा उच्च अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय खात्र निगम की सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करनी है।

[सं० फा० 10-3/70-एफ० सी० सी०]

के० पा० मथरानी,
सचिव, भारत सरकार।